

प्रेषक,

डा०एम०सी०जोशी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून दिनांक 22 दिसम्बर, 2014

विषय:-श्री देव पब्लिक हाईस्कूल, अम्बूवाला पथरी, जनपद हरिद्वार को अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-06(03)/57/30292/2013-2014, दिनांक 01 अक्टूबर, 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, श्री देव पब्लिक हाईस्कूल, अम्बूवाला पथरी, जनपद हरिद्वार को हाईस्कूल स्तर पर अनुदान सूची में सम्मिलित करते हुए इस विद्यालय हेतु निम्न तालिका में इंगित अस्थाई पदों/पदस्थानों को शासनादेश निर्गत होने अथवा नियमित नियुक्ति होने, जो भी बाद में हो, से दिनांक 28 फरवरी, 2015 तक बशर्ते कि यह पद बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाये, सृजित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान	सृजित होने वाले पदों की संख्या-
1	2	3	4
1.	प्रधानाध्यापक	15600-39100 ग्रेड पे-5400	01 पद (जूनियर हाईस्कूल से समायोजित)
2.	स०अ०एल०टी०	(9300-34800) ग्रेड पे 4600	07 पद (04 पद जूनियर हाईस्कूल से समायोजित)
		कुल पद	08 (आठ पद)

3. उपर्युक्त पदों पर चयन की कार्यवाही उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये विनियम-2009 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।



4. उपर्युक्त तालिका में अंकित पदों का सृजन इस शर्त के साथ अनुमन्य होगा कि विद्यालय में वास्तविक आवश्यकता, वर्तमान में छात्र संख्या एवं संबंधित पद धारक प्रति वादन पढ़ाई हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करते हों, तथा इसका परीक्षण जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. उक्त विद्यालय में यदि किन्हीं प्रतिबन्धों/शर्तों की पूर्ति अवशिष्ट हो, तो उन्हें एक निर्धारित अवधि के भीतर संस्थाधिकारी को शर्तों/प्रतिबन्धों की पूर्ति के निर्देश दे दिये जाय।
6. उपर्युक्त पदों के सापेक्ष चयन प्रक्रिया उमादेवी वाद में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप एवं नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित पदों को शासन द्वारा अनुमन्य वेतन, महगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
8. यदि विद्यालय के लेखे एवं वित्तीय मामलों में गम्भीर अनियमितताएं हों तो अनुदान सूची में लेने के 02 वर्ष के अन्दर इन कमियों को दूर करना अनिवार्य होगा। यदि 02 वर्ष के भीतर विद्यालय द्वारा कमियों को दूर नहीं किया गया तो उन्हें अनुदान सूची से बहिष्कृत कर दिया जायेगा।
9. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-11 के आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-02-माध्यमिक शिक्षा-110-गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता-04-अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता-0403-सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त वेतन भुगतान हेतु अनुदान-43-वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान के नामे डाला जायेगा।
10. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-245(p)/XXVII(3)/2014-15 दिनांक 15 दिसम्बर 2014 में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
(डा०एम०सी०जोशी)  
सचिव।

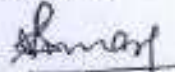
संख्या-698(1)/XXIV-4/2014, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा०मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मा० शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा० शिक्षा मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
4. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।

6. मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार।
8. जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
9. सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाध्यापक।
10. वित्त विभाग/नियोजन प्रकोष्ठ।
11. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(श्रीप्रकाश तिवारी)  
अनुसचिव।